संदेश

(जनता के लिए)

# 2022 सितंबर 21 से 27 तक
# पार्टी की 18वीं वर्षगांठ को देशभर में
# क्रांतिकारी उत्साह व दृढ़संकल्प के साथ मनाएं!

## जनाधार बढ़ाते हुए जनयुद्ध को आगे बढ़ाएं!
## दुश्मन का रणनीतिक 'समाधान'–प्रहार हमले को परास्त करें!

*पार्टी की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर*
*पार्टी कतारों और क्रांतिकारी जन निर्माणों तथा जनता को*
*भाकपा (माओवादी) केंद्रीय कमेटी का संदेश!*

केंद्रीय कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

# 2022 सितंबर 21 से 27 तक
# पार्टी की 18वीं वर्षगांठ को देशभर में
# क्रांतिकारी उत्साह व दृढ़संकल्प के साथ मनाएं!
# जनाधार बढ़ाते हुए जनयुद्ध को आगे बढ़ाएं!
# दुश्मन का रणनीतिक 'समाधान'–प्रहार हमले को परास्त करें!

**प्यारे कामरेडो व जनता!**

भारत के क्रांतिकारी सर्वहारा के अगुवे दस्ते के रूप में भारतीय क्रांति का नेतृत्व करने वाली हमारी पार्टी – भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की स्थापना को आगामी 21 सिंतबर, 2022 तक 18 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इस अवसर पर केंद्रीय कमेटी पार्टी की सभी कतारों, क्रांतिकारी जन निर्माणों एवं जनता का आह्वान करती है कि वे पार्टी की 18वीं वर्षगांठ को 21 से 27 सिंतबर, 2022 तक देशभर के देहाती इलाकों, कस्बों व शहरों में क्रांतिकारी उत्साह व दृढ़संकल्प के साथ मनाएं और देशभर में जनाधार बढ़ाते हुए, पार्टी को मजबूत करते हुए भारत का जनयुद्ध को आगे बढ़ाएं और प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक 'समाधान'–प्रहार हमले को परास्त करें!

हमारे देश में सड़ी–गली अर्धऔपनिवेशिक व अर्धसामंती व्यवस्था को ध्वस्त कर, नवजनवादी क्रांति को सफल बनाना और विश्वभर में समाजवाद व साम्यवाद को स्थापित करने के लक्ष्य से काम करना – इन महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़संकल्प के साथ कार्यरत हमारी पार्टी एवं क्रांतिकारी आंदोलन को उन्मूलन करने के उद्देश्य से दुश्मन द्वारा चलाए जा रहे 'समाधान'–प्रहार हमलों को साहस व धैर्य के साथ सामना करते हुए पिछले एक वर्ष के दौरान 124 कामरेड शहीद हुए. इनमें से 30 महिला वीर योद्धा शामिल हैं. अमर शहीदों में हमारी केंद्रीय कमेटी व पोलित ब्यूरो के सदस्य कामरेड रामकृष्णा (अक्किराजू हरगोपाल, साकेत), केंद्रीय कमेटी के सदस्य एवं महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ स्पेशल जोन कमेटी के सचिव कामरेड दीपक (मिलिंद तेलतुम्ड़े), दंडकारण्य एसजडसी सचिवालय सदस्या कामरेड नर्मदा (उप्पुगंटी निर्मला), बिहार–झारखंड सैक सचिवालय सदस्य कामरेड रूपेश (संदीप यादव), जडसी/डीवीसी/डीसी के 13 कामरेड, 30 एसी/पीपीसी के सदस्य, 25 पार्टी व पीएलजीए सदस्य और जन निर्माणों के 27 कार्यकर्ता

शामिल हैं. और 25 कामरेडो का ब्योरा पहुंचना बाकी है. इनके अलावा समूचा देश में खुले जन आंदोलनों में कार्यरत कई क्रांतिकारी, प्रगतिशील व जनवादी जन संगठनों के नेतृत्व व कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, क्रांतिकारी हमदर्दों व मित्रों का निधन हुआ. पार्टी की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर, हमारी पार्टी के प्यारे संस्थापक नेताद्वय कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी समेत, जनता की मुक्ति के लिए अपनी जान कुरबान देने वाले तमाम अमर शहीदों को केंद्रीय कमेटी सिर झुकाकर विनम्रता से क्रांतिकारी जोहार अर्पित करती है.

पेरू कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कामरेड गोंजालो, फिलिप्पींस के एनपीए के प्रवक्ता कामरेड का ओरिस और गलीसिया माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता कामरेड मार्टिन नया समेत कई नेतृत्व कामरेडो की शहादत अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए बड़ा नुकसान है. कामरेड गोंजालो मालेमा सिद्धांत और दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन को पेरू की सामाजिक परिस्थितियों से अनुप्रयोग करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वहां के जनयुद्ध को आगे बढ़ाने में महान नेता बने. साम्राज्यवाद के खिलाफ विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाएं महत्वपूर्ण हैं. फिलिप्पीनी क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह उन्मूलन करने के लक्ष्य से अमेरिकी साम्राज्यवादियों के दिशानिर्देशन में दलाल शासकों की प्रतिक्रांतिकारी दमन अभियान का मुकाबला करने में एनपीए के वरिष्ठ कमांडर और प्रवक्ता के बतौर कामरेड का ओरिस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा आंदोलन में मिगइल अलोन्सो के नाम से प्रसिद्ध कामरेड मार्टिन नया (62) का निधन तीव्र अस्वस्थता की वजह से 3 सितंबर, 2021 को हुआ. उन्होंने पिछले चार दशकों से मालेमा लाल परचम को ऊंचा उठाकर गलीसिया मजदूर संगठन के नेता व मालेमा पार्टी के नेता के रूप में अंतरराष्ट्रीय और देशीय तौर पर कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास के लिए अविराम प्रयास किया. सर्वहारा के इन महान नेताओं के अलावा विश्व समाजवादी क्रांति के तहत विभिन्न देशों में जारी नवजनवादी व समाजवादी क्रांतियों में, विभिन्न साम्राज्यवाद–विरोधी, राष्ट्रीय–मुक्ति आंदोलनों में और जनवादी, प्रगतिशील व देशभक्तपूर्ण आंदोलनों में अपने प्राण न्योछावर करने वाले तमाम वीर योद्धाओं को केंद्रीय कमेटी क्रांतिकारी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है. आइएं! वीर शहीदों की आदर्शमय सर्वहारा जीवनियों से प्रेरणा लेकर, उनके आदर्शों, निस्वार्थ एवं आत्मबलिदान की चेतना से आत्मसात करते हुए, उनके नक्षे कदम क्रांतिकारी

रास्ते पर अडिग होकर अंतिम मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए अंतिम सांस तक लड़ने की शपथ लेते हैं.

इस वर्ष दुश्मन के 'समाधान'–प्रहार हमलों का वीरतापूर्वक सामना कर, उनकी योजनाओं का नाकाम करने के दौरान घायल हुए तमाम वीर योद्धाओं के प्रति केंद्रीय कमेटी प्रगाढ़ सहानुभूति व्यक्त करती है और प्रगाढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र स्वस्थ होकर जनयुद्ध के मैदान में कूद पड़ेंगे. इस वर्ष के दौरान हमारी पार्टी के वरिष्ठ कामरेड, पोलिट ब्यूरो के सदस्य एवं पूर्वी रीजिनल ब्यूरो के सचिव कामरेड किशन दा, सीसी के सदस्य कामरेड्स शीला दी, कंचन दा, कृष्णमूर्ति और जशपाल जी की गिरफ्तारियां हुईं. इन गिरफ्तारियों से भारत की नवजनवादी क्रांति को आगे बढ़ाने का कार्य पर नकारात्मक असर हो रहा है. कई कामरेड दुश्मन के चंगुल में फंसकर यातनाएं झेलकर, झूठे मुकद्दमों पर जेलों में बंद हैं, बिहार व झारखंड राज्यों में फासीवादी जजों ने कुछ कामरेडो को फांसी की सजा सुनायी. सैकड़ों कामरेड और क्रांतिकारी किसान कार्यकर्ता सजा काट रहे हैं. ये तमाम कामरेड कालकोठरियों को संघर्ष के केंद्र के रूप में तब्दील करते हुए क्रांति का झंडे को ऊंचा उठाए रखे हुए हैं. इन तमाम साथियों को केंद्रीय कमेटी जय–जयकार करती है और उन्हें यह भरोसा देता है कि उनकी त्वरित रिहाई के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी.

पार्टी की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न इलाकों की ठोस परिस्थितियों के अनुसार दुश्मन का 'समाधान'–प्रहार हमले का सामना करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन के विकास के लिए केंद्रीय कमेटी द्वारा कर्तव्य तय किए गए. इन कर्तव्यों को पूरा करने में पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हमारे द्वारा हासिल विकास व परिणामों पर नजर डालेंगे.

**पार्टी:** जनवरी 2021 में हमारी कंद्रीय कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयों को इस वर्ष के दौरान लागू करने के लिए देशभर में ऊपर से नीचे तक के हमारी पार्टी, पीएलजीए और क्रांतिकारी जन निर्माणों द्वारा प्रयास किए गए. कमेटियों में टीम वर्क करने में अपेक्षाकृत बेहतरी आयी है. लेकिन व्यक्तिगत व सामूहिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. कमेटियों का कामकाज में और बेहतरी हासिल करने और कमेटियों के सोच–विचार में एकता बढ़ाने की जरूरत है. इसके लिए मालेमा की रोशनी में जनवादी केंद्रीयता को उसकी असली अर्थ के साथ परिस्थितियों के अनुरूप सृजनात्मक रूप से अनुप्रयोग करते हुए सही विचारों को विकसित करने के लिए आत्मालोचना–आलोचना पद्धति को तेज हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में कुछ बेहतरी हासिल हुई

है. पार्टी की लाइन व कार्यनीति पर निर्भर होकर ऊपर से नीचे तक तमाम पार्टी कतारों, पीएलजीए व क्रांतिकारी जन निर्माणों को एकताबद्ध करने, उन्हें व्यापक जनता में ले जाने और मजबूत व संगठित शक्ति के रूप में उन्हें तब्दील करने पर कुछ प्रयास हुआ. लेकिन पार्टी के सोच–विचार में एकता, व्यवहार में एकता और अनुशासन के साथ विकसित करने में, भगोड़ापन को जड़ से उखाड़ने में और कम्युनिस्ट मूल्यों को बढ़ाने में बहुत कुछ करना बाकी है.

इस वर्ष के दौरान पार्टी का संगठितीकरण अभियान चलाया गया. विभिन्न पार्टी कमेटियों द्वारा ठोस परिस्थितियों के मुताबिक सर्कुलर जारी कर संगठितीकरण कार्यक्रम अपनाया गया. केंद्रीय कर्तव्य को पूरा करने के लिए ताकत के मुताबिक तीन क्रांतिकारी जादुई हथियारों को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है. पार्टी, विशेषकर नेतृत्व की रक्षा पर महत्व दिया गया. संगठितीकरण के तहत कुछ इलाकों में पार्टी की सदस्यता कुछ बड़ी है. नये पार्टी सेलों का निर्माण और धक्का खाए हुए पार्टी सेलों का पुनर्निर्माण किया गया. उनका कामकाज चलाते हुए स्थानीय स्तर पर जनयुद्ध के काबिल नेतृत्व की तरह उन्हें शिक्षा दिलाने का प्रयास हुआ. विभिन्न स्पेशल एरिया/स्पेशल जोन/राज्यों की प्लीनम समीक्षाओं और कर्तव्यों पर अपनी कतारों को शिक्षित की गयी. पार्टी दस्तावेजों – 'भारत देश में उत्पादन संबंधों में बदलाव–हमारा कार्यक्रम' (MOP), 'भारत देश में राष्ट्रीयताओं का सवाल–हमारा दृष्टिकोण' और 'केंद्रीय कमेटी की राजनीतिक व सांगठनिक समीक्षा' (CC POR) पर नीचे तक शिक्षा दिलाने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन, अध्ययन शिविर और अध्ययन कक्षाओं की प्रक्रिया चल रही है. विभिन्न स्परूपों में इस शिक्षा को जन संगठनों तक और जनता तक ले जानी होगी. एमओपी दस्तावेज पर आधारित होकर वस्तुगत स्थिति के अनुसार कार्यनीति, यानी वर्गसंघर्ष के कार्यक्रम बनाकर दृढ़ दीक्षा के साथ लागू करने के लिए हमारी पार्टी होने वाले हर एक इलाके में प्रयास करना चाहिए.

समूचा देश में दलाल शासक वर्गों द्वारा चलाए जा रहे भीषण प्रतिक्रांतिकारी व राणनीतिक 'समाधान'–प्रहार हमले का पारेवा जैसे घटनाओं में साहसिक रूप से प्रतिरोध करते हुए पार्टी द्वारा अत्यंत उच्च बलिदान की परंपराओं को खड़ा किया गया. इसके बावजूद बदलती परिस्थितियों के अनुसार कामकाज में बदलाव नहीं कर पाने की वजह से पार्टी ने बहुत गंभीर नुकसान उठाना पड़ा. इन नुकसानों को ध्यान में रखकर उनसे बचने के लिए जनवरी 2022 में हमारी

पार्टी के पोलिट ब्यूरो ने एक सर्कुलर जारी किया. उसमें यह आह्वान किया गया कि दुश्मन की रणनीतिक व कार्यनीतिक योजना को अध्ययन करने में, समझने में, हमारा व्यवहार में जारी कमी–कमजोरियों को चिन्हित किया जाए, उन्हें सुधारने, उनसे उबरने के लिए ठोस रूप से और घटनावार नीचे से समीक्षाएं करवायी जाए व सबकें ली जाए और उन्हें दृढ़ता से लागू किया जाए. उसके अनुरूप पूरी पार्टी में अभी ठोस प्रयास बढ़ाने की जरूरत है.

पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य कोबाड घैंडी द्वारा पार्टी, मालेमा सिद्धांत और क्रांतिकारी आंदोलन की गद्दारी कर 'फ्रैक्चर्ड् फ्रीडम् ए प्रिज़न मेम्वार' नाम पर जारी की गयी पुस्तक का जवाब देते हुए केंद्रीय कमेटी ने एक सैद्धांतिक पुस्तिका जारी की और स्पष्ट किया कि कोबाड की पुस्तक गद्दारी की दस्तावेज़ है. उन्हें पार्टी से बहिष्कार किया और आह्वान किया कि पार्टी की केंद्रीय कमेटी सदस्य के रूप में रहते हुए गिरफ्तार होने के बाद क्रांति के प्रति गद्दार बने कोबाड को नकारात्मक शिक्षक के रूप में लिया जाए.

आंध्रप्रदेश के क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास में सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी ही तरह के क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाली और गौरवशाली स्थान हासिल करने वाली जन नाट्य मंडली का इतिहास को पार्टी ने प्रकाशित की. जन नाट्य मंडली द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए अनमोल अनुभव उस क्षेत्र के विकास में और उस क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों से उबरने में मदद करेगी.

इस दौर में साम्राज्यवादियों व दलाल शासक वर्गों के हितों को पूरा करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जनता के खिलाफ लाए गए कई नए कानूनों व नीतियों का पर्दाफाश करते हुए हमारी पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेप किया. पार्टी ने अपने प्रचार व आंदोलन के कार्यक्रमों में कुछ बदलाव ला रही है. सोशल मीडिया का कुछ हद तक इस्तेमाल किया जा रहा है. पार्टी की केंद्रीय पत्रिकाओं और विभिन्न राज्यों की पत्रिकाओं को समय पर निकालने में अपेक्षाकृत बेहतरी आयी है. पीएलजीए की 20वीं वर्षगांठ के समापन के दौरान सोवनीर और अवामी जंग का विशेष अंक समेत विभिन्न राज्यों की पत्रिकाओं के विशेष अंक प्रकाशित हुए. केंद्रीय कमेटी ने हमारी पार्टी के एक संस्थापक नेता व शिक्षक कामरेड कन्हाई चटर्जी की संक्षिप्त जीवनी को प्रकासित की. एकता पार्टी के गठन से लेकर 2014 तक केंद्रीय कमेटी के शहादत प्राप्त सदस्यों की जीवनियों का संकलन–1 को हिंदी भाषा में प्रकाशित की.

इस वर्ष के दौरान हमारी केंद्रीय कमेटी ने अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारी सर्वहारा आंदोलन के क्षेत्र में विभिन्न स्वरूपों में अपने प्रयास को विस्तारित किया. पार्टी ने '24 नवंबर कार्य दिवस' पर भारत के जनयुद्ध की अंतरराष्ट्रीय भाईचारा कमेटी (ICSPWI) का आह्वान पर, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आदि क्रांतिकारी दिवसों पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास किया. 29 मार्च को एनपीए की 53वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर फिलिप्पींस के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति भाईचारा कार्यक्रम चलाया गया. युक्रैन पर रूसी दुराक्रमण युद्ध पर हमारी पार्टी का रुख विश्व की जनता के सामने रखा गया. विश्व सर्वहारा का दीक्षा दिवस 'मई दिवस' (1 मई) के अवसर पर हमारी केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी किया गया वक्तव्य पर विभिन्न देशों की 13 मालेमा पार्टियां सहमति जताने के बाद वह संयुक्त वक्तव्य का रूप ले लिया. 1 जुलाई को भारत के जनयुद्ध की अंतरराष्ट्रीय भाईचारा कमेटी (ICSPWI) की बैठक व 2–3 जुलाई को मालेमा पार्टियों का अंतरराष्ट्रीय बैठक जो आयोजित की गयी, उनके लिए हमारी केंद्रीय कमेटी का संदेश पहुंचाया गया और हमारी पार्टी की दस्तावेज़ 'सर्वहारा के अंतरराष्ट्रीय संगठन गठित करने पर हमारी पार्टी का दृष्टिकोण' को उन बैठकों के सामने रखी गयी. उस बैठक में जो निर्णय लिए गए, यानी मालेमा पार्टियों द्वारा साम्राज्यवाद के खिलाफ, भारत के जनयुद्ध के समर्थन में साझा कार्यक्रम अपनाते हुए ही, अंतरराष्ट्रीय संगठन को गठित करने के मामले पर एक साझा समझदारी बनाने की दिशा में प्रयास जारी रखा जाए, आदि से हमारी पार्टी ने अपनी सहमति जतायी. हमारे तमाम अंतरराष्ट्रीय प्रयास में शामिल आईसीएसपीडब्ल्यूआई का भाईचारा प्रयास सराहनीय है. विश्व के विभिन्न मालेमा पार्टियों द्वारा चलाए जा रहे यह प्रयास विश्व समाजवादी क्रांतिकारी शक्तियों की पुनःगोलबंदी में, संगठितीकरण में, क्रांतिकारी आंदोलनों को आगे बढ़ाने में अवश्य मदद करेगी.

**पीएलजीएः** इस वर्ष के दौरान हमारी पार्टी के नेतृत्व में गुरिल्ला इलाकों में पीएलजीए बलों द्वारा दुश्मन का भीषण प्रहार हमले का साहसिक रूप से मुकाबला करने के लिए अलग–अलग स्तर पर गुरिल्ला युद्ध चलाया गया. अस्थायी तौर पर पीछे हटने की स्थिति से उबार कर क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद हो, इसके लिए अपेक्षाकृत जनकार्य बढ़ाया गया. जनता को साम्राज्यवाद–विरोधी, दलाल नौकरशाह पूंजीपति व सामंत–विरोधी वर्ग संघर्षों में गोलबंद व संगठित करने में और जुझारू जनांदोलनों का निर्माण करने में पीएलजीए ने सक्रिय रूप से शामिल हुई. विभिन्न क्रांतिकारी जन

संगठनों और क्रांतिकारी जन राजसत्ता की इकाइयों का निर्माण व पुनर्निर्माण के समर्थन में अपना बल के साथ खड़े रहे . विभिन्न पार्टी कमेटियों, मिलिटरी कमिशनों व कमानों के नेतृत्व में कुछ इलाकों में कार्यनीतिक जवाबी हमले के अभियानों (TCOCs) और गुरिल्ला कार्रवाइयों को संचालित कर कुछ सफलताएं हासिल की गयी. झारखंड में मनोहरपुर विधायक के सुरक्षा गार्डों पर हमले कर दो गार्डों का सफाया और तीन एके रायफलों की जब्ती, ओड़िशा में नुवापाड़ा–पाताधारा सरप्राइज एम्बुश में दो एएसआई समेत तीन सीआरपीएफ जवानों का सफाया व सात जवानों को घायल करना और तीन एके रायफलों की जब्ती जैसे कुछ महत्वपूर्ण गुरिल्ला कार्रवाइयां हुईं. दंडकारण्य में विभिन्न गुरिल्ला कार्रवाइयों में 9 अर्धसैनिक, स्पेशल पुलिस वालों का सफाया कर 34 अर्धसैनिक, स्पेशल पुलिस वालों को घायल किया गया. पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न गुरिल्ला इलाकों में पीएलजीए द्वारा संचालित गुरिल्ला कार्रवाइयों में 13 अर्धसैनिक, कमांडो व स्पेशल पुलिस वालों का सफाया कर, 54 अर्धसैनिक, कमांडो व स्पेशल पुलिस वालों को घायल किया गया. पांच जनविरोधी राजनेताओं, 34 पुलिस मुखबिरों, दो गद्दारों और एक जन–दुश्मन का सफाया किया गया. गुरिल्ला युद्ध में हासिल किए गए इन सफलताओं से क्रांतिकारी उत्साह बढ़ाने और दुश्मन का हमले को एक हद तक रोकने में मदद मिली.

पीएलजीए बलों को मजबूत करने के लिए विभिन्न पार्टी कमेटियों द्वारा कई राजनीतिक कक्षाएं और मिलिटरी प्रशिक्षण कैंप संचालित किए गए. उन्हें पार्टी बुनियादी दस्तावेजों पर प्राथमिक समझदारी दिलाने का प्रयास किया गया. विभिन्न किस्म के कंबैट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और इंप्रूवाइज्ड हथियारों का इस्तेमाल पर विभिन्न स्तरों में पीएलजीए के प्रधान व द्वितीय बलों और बुनियादी बल मिलिशिया को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. स्थानीय संसाधनों पर निर्भर होकर पीएलजीए बलों को हथियारबंद करने का प्रयास किया जा रहा है. इसमें विभिन्न स्तरों की पार्टी कमेटियां, मिलिटरी कमिशनों, कमानों, मिलिटरी इंस्ट्रक्टर टीमों और विभागों ने मुख्य भूमिका निभा रही है. गुरिल्ला इलाकों में दुश्मन के फासीवादी हमले से पीएलजीए बलों, अनुबंध विभागों को संरक्षित करने, कमजोर होने वाली यूनिटों को मजबूत करने, नुकसान झेलने वाली यूनिटों को पुनर्निर्माण करने और आवश्यक नयी यूनिटों का निर्माण करने, आंदोलन को बरकरार रखने व विस्तार करने के लिए पार्टी द्वारा योजनाबद्ध ढंग से प्रयास किया जा रहा है. पार्टी व पीएलजीए से निष्क्रिय हुए गद्दारों की

विघटनकारी कार्रवाइयों पर रोक लगाते हुए पार्टी, जनता और आंदोलन को संरक्षित किया जा रहा है.

**संयुक्त मोर्चाः** जनवरी 2021 में हमारी केंद्रीय कमेटी ने यह आकलन लगाया कि देश में पिछले पांच वर्षों से चल रहे कई जनांदोलन देशव्यापी 'जनांदोलन की ज्वार' के रूप में तब्दील हो सकती है. जनांदोलनों का उभार जो चल रहा है, इससे साबित होता है कि यह आकलन सही है. दुश्मन के फासीवादी दमन के बीच ही पार्टी द्वारा निरंतर साहसिक ढंग से उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित तबकों के प्रचार–आंदोलनों का निर्माण, विभिन्न जन संगठनों का निर्माण व विकास के लिए जहां–तहां योजनाएं बनाकर लागू करने का प्रयास किए जा रहे हैं. विभिन्न इलाकों में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवादी व सामंतवादी वर्गों के खिलाफ वर्ग संघर्ष निर्माण करने में अपेक्षाकृत कुछ विकास हासिल किया गया. समूचा देश में और क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में कार्पोरेटीकरण व सैन्यकरण (कार्पेट सेक्युनिटी का विस्तार) एवं जबरन विस्थापन के खिलाफ जनता हजारों की संख्या में गोलबंद हो रही है. आंदोलनरत जनता की राजनीतिक चेतना बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी तमाम इलाकों में पहलकदमी लेकर प्रयास करने की जरूरत है.

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एवं कृषि क्षेत्र का कार्पोरेटीकरण के खिलाफ देश राजधानी दिल्ली को केंद्र बनाकर एक वर्ष से अधिक समय तक चलाए गए किसान आंदोलन में हमारी पार्टी ने अपनी शक्ति के मुताबिक शामिल हुई. देश के मजदूर, छात्र, जनवादी ताकतों, तमाम उत्पीड़ित वर्गों, तबकों व राष्ट्रीयताओं की जनता के समर्थन प्राप्त कर किसानों द्वारा चलाए गए जुझारू आंदोलन से मोदी सरकर तीन कृषि कानूनों को वापस लेने में मजबूर हुई. इस आंदोलन की जीत से संयुक्त मोर्चा के क्षेत्र में हमारी पार्टी ने एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया.

विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और टाटा, अड़ानी, अंबानी, वेदांता, जिंदल, मित्तल, एस्सार, लायड जैसे देशीय दलाल नौकरशाह पूंजीपति कंपनियों, विभिन्न सरकारों द्वारा प्रस्तावित खदानों व परियोजनाओं के लिए, विभिन्न कार्पोरेट–प्रायोजित व जनविरोधी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण के लिए व अभयारण्यों के लिए जबरन किसानों की जमीन, सरकारी जमीन, हसदेव अरण्य जैसे वन क्षेत्रों को हड़पने के खिलाफ, जबरन विस्थापन के खिलाफ, पर्यावरण का विनाश के खिलाफ कई आंदोलन चलाए गए. राज्यहिंसा के खिलाफ, कार्पोरेट कंपनियों की रक्षा के लिए तैनात लाखों पुलिस बलों व कैंपों को वापस

लेने, भीमा कोरेगांव जैसे कई षड़यत्र मामलों में जेलों में बंदी बनाए गए राजनीतिक कैदियों की रिहाई करने, 'उपा' जैसे क्रूर कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन चलाए गए और क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में अनिश्चितकालीन आंदोलनों का उभार आया. विशेषकर 'जल–जंगल–जमीन' पर आदिवासियों व उत्पीड़ित जनता के अधिकार के लिए, आदिवासी इलाकों में 5वीं अनुसूची व 6वीं अनुसूची को लागू करने, ग्रामसभाओं को अधिकार देने, मूलवासी–आदिवासी इलाकों को स्वायत्तता देने की मांग को लेकर, वन सुरक्षा कानून–1980 को कमजोर करने वाले प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ, आदिवासी इलाकों में 'माओवादियों का उन्मूलन' के नाम पर मनमानी ढंग से किए जाने वाले ड्रोन हमलों के खिलाफ, 'बस्तर में नरसंहार बंद करो', 'नरसंहारों के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को कड़ी सजा दो' की मांगों को लेकर, कई जगहों पर हजारों जनता लड़ रही है. विशेषकर दंडकारण्य में आदिवासी जनता व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाकर उसके नेतृत्व में सिलगेर में पुलिस कैंपों, अत्याचारों व हत्यकांडों के खिलाफ जुझारू रूप से अनिश्चितकालीन आंदोलन एक वर्ष से जारी है. इसके समर्थन में न सिर्फ समचे छत्तीसगढ़ राज्य में भाईचारा आंदोलन का विस्तार हुआ, बल्कि देश व दुनिया में भी समर्थन प्राप्त करने में वह एक नमूना बन गया. झूम खेतों को बचाने के लिए तेलंगाना में आदिवासी लंबे समय से लड़ रहे हैं. वन क्षेत्रों में फारेस्ट अधिकारियों के हमलों के खिलाफ जन गोलबंदियां हुई हैं. कुछ इलाकों में पार्टी ने जंगल जमीन व बंजर जमीन की जब्ती आंदोलनों का नेतृत्व किया. किसानों की समस्याओं पर जहां–तहां जनता आंदोलनों में एकत्रित हुई. इन आंदोलनों के क्रम में पार्टी ने विभिन्न स्वरूपों में राजसत्ता दखल करने की सशस्त्र संघर्ष की राजनीति से जनता को जागरूक किया.

मोदी सरकार द्वारा बनाए गए मजदूर–विरोधी चार संविदा को वापस लेने की मांग को लेकर, बैंक, रेलवे, एलआईसी, खदान, स्टील प्लांट आदि तमाम सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं व कंपनियों की निजीकरण के खिलाफ संगठित व असंगठित क्षेत्रों के मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, अंगनवाड़ी, प्रवासी व विस्थापित मजदूर व युवा, आदि द्वारा चलायी जा रही हड़तालों व बंदों का पार्टी ने समर्थन किया. केरल के कोझिक्कोड जिले में प्रस्तावित सिल्वर लाइन सेमी–हाई स्पीड रेलवे कॉरिडार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जारी आंदोलन का पार्टी ने समर्थन किया. ओडिशा के नवरंगपुर जिले में तेल नदी पर प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना का निर्माण के खिलाफ जनता ने आंदोलन की तैयारी

कर रही है. उक्त तमाम आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी है. इसके अलावा महिलाओं पर जारी घोर अत्याचारों के खिलाफ वे कई आंदोलनों में जुझारू रूप से गोलबंद हो रही हैं. ओडिशा के रायगड़ा जिले में स्कूल शिक्षिका ममिता मेहर की हत्या व उसकी लाश जलाकर दफनाने की घटना, केरल में एक नन पर अत्याचार के मामले में कोर्ट ने बिशप को निर्दोष ठहराकर रिहाई करने वाली घटना, आदि के खिलाफ महिलाएं जुझारू रूप से सड़कों में आयी हैं. जनता की दैनंदिन समस्याओं पर, विशेषकर युक्रैन पर रूस का दुराक्रमण के बाद दुनिया भर में और देश में आसमान छूने वाली मूल्यों के खिलाफ कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए.

धार्मिक अल्पसंख्यकों पर, विशेषकर मुस्लिमों पर, इसाइयों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर, महिलाओं पर, छात्र–बुद्धिजीवियों पर ब्राह्मणीय हिंदुत्व शक्तियों द्वारा चलाए जा रहे अत्याचारों एवं हत्याकांडों के खिलाफ कई आंदोलन जारी हैं. देश में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे गरीब जनता खाद्य सुरक्षा अधिकार के लिए लड़ रहे हैं. देश में कई शहरों में मानवाधिकार संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रमुख प्रोफेसरों, इतिहासकारों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, सामाजिक शोधकर्ता 'जनतंत्र बचाओ' का नारा को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं. सवाल उठाने वाले आवाजों पर 'अर्बन नक्सल' का ठप्पा लगाकर राजसत्ता द्वारा चलाए जा रहे क्रूर दमन के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं. शिक्षा क्षेत्र का भगवाकरण एवं कार्पोरेटीकरण करने वाली नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ, सार्वजनिक शिक्षा अधिकार के लिए और आनलाइन शिक्षा नीति के खिलाफ और बड़े पैमाने पर बढ़ रहे बेरोजगारी के खिलाफ कई आंदोलनों में छात्र–युवा और शिक्षक गोलबंद हो रहे हैं. भारतीय सेना का भगवाकरण व कैजुअलीकरण के लिए हिंदुत्व मोदी सरकार लागू की जा रही 'अग्निपथ' योजना के खिलाफ बेरोजगार युवा देशभर में बगावत किया.

इस तरह के कई आंदोलनों का हमारी पार्टी ने न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि जहां पार्टी का काम जारी है, वहां उन आंदोलन में हिस्सा लिया और उनका नेतृत्व करने का प्रयास किया. इस क्रम में विभिन्न राज्यों में पार्टी के नेतृत्व में कई जन संगठन अपने अधिवेशनों का आयोजन कर भविष्य के कर्तव्य तय किया और राजनीतिक व सांगठनिक रूप से संगठित हुए. विभिन्न खुला व गुप्त जन संगठन व संयुक्त मार्चे गठित होकर काम करने में कुछ वृद्धि आयी. उत्पीड़ित वर्गों, तबकों व राष्ट्रीयताओं की जनता की आकांक्षाओं के अनुसार उन्हें नेतृत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक अध्ययन एवं स्पेशलाइजेशन

विकसित करने के लिए पार्टी प्रयासरत है. किसान समस्याओं पर सांगठनिक तौर पर प्रयास हो रहे हैं.

पार्टी के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध जहां तीव्र स्तर पर जारी है, वहां क्रांतिकारी जन राजसत्ता की इकाइयां ग्राम, एरिया व जिला स्तरों में काम कर रही हैं और प्राथमिक स्तर पर जन राजसत्ता चला रही हैं. क्रांतिकारी जनता इन जन सरकारों को बचाते हुए अपना भविष्य खुद तय कर रही हैं. भ्रूण रूप में वैकल्पिक विकास का नमूना जनता के सामने ला रही हैं. झारखंड व ओडिशा में पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने का पार्टी का आह्वान को लेकर कई गांवों में जनता स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट न देकर अपना विरोध जताया और क्रांतिकारी विकल्प की तरफ संगठित हो रहे हैं.

**प्यारे कामरेडो व जनता!**

अंतरराष्ट्रीय तौर पर 2008 से जारी आर्थिक मंदी में अल्पकालीन वापसी करने के बावजूद, साम्राज्यवादी वित्तीय व आर्थिक संकट तेज होती जा रही है. इससे उबरने के लिए, विश्व को अपनी शक्ति–संतुलन के अनुसार विभाजित कर लूटने के लिए साम्राज्यवादियों ने वैश्वीकरण नीतियां अपना रहे हैं. फलस्वरूप, नया औपनिवेशिक शोषण और बढ़ी है. अमीर व गरीब के बीच अंतर पहले के मुकाबले बहुत बढ़ी हैं. पिछड़े हुए एशिया, अफ्रीका व लातीन अमेरिका के देश पूरी तरह पराधीन देश के रूप में तब्दील हो गए.

सोमालिया, इथियोपिया, दक्षिण सूड़ान, येमन, अफ्गानिस्तान जैसे कई पिछड़े हुए देशों में बाह्य व आंतरिक संघर्षों के अलावा पर्यावरण की संकट से प्राकृतिक विपदाएं, कोविड जैसे जानलेवा बीमारियां, मूल्य वृद्धि के कारण विश्व में 34.5 करोड़ गरीब जनता खाली पेट, आधा भूख व बीमारियों से जीवन व मृत्य के बीच जूझ रही है. साम्राज्यवाद–प्रायोजित वैश्वीकरण नीतियों के फलस्वरूप दलाल शोषक–शासकों द्वारा बची–खुची जन कल्याण व्यवस्थाओं का ध्वस्त किए जाने के कारण कई गरीब लोग निस्सहाय होने की स्थिति में आत्महत्या कर रहे हैं. हर रोज 8,500 बच्चे पोषकाहार की कमी से मर रहे हैं. एक आकलन के मुताबिक 1960वें दशक के बाद कभी नहीं होने वाली भुखमरी वर्ष 2022–23 में हो सकता है. गरीबों का आय घट रहा है, रोजमर्रा के चीजों की मूल्य में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो रही है.

इन संकटों के दौरान युक्रैन युद्ध आग में घी का काम किया और विश्व के कई देशों के आर्थिक व्यवस्थाओं को और संकट में धकेल दिया. अमेरिका व

यूरोप देश अपने साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने के लिए रूस पर हजारों पाबंदियां लगाने की वजह से कई मुख्य उत्पादनों, कच्चे पदार्थों एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला नष्ट हो गया, इससे विश्वभर में आर्थिक संकट और तेज होती जा रही है. इससे पहले ही रूस में तीव्र आर्थिक मंदी बनी हुई है. अमेरिका में भी मुद्रास्फीति 41 वर्षों का रिकार्ड तोड़कर नया रिकार्ड बनाया. दुनिया खाद्य संकट में फंसती जा रही है. बेरोजगारी बढ़ रही है. एक तरफ साम्राज्यवादियों व दलाली शोषकों ने युक्रैन से अप्रत्याशित मुनाफे कमा रहे हैं, दूसरी तरफ करोड़ों उत्पीड़ित जनता खाद्य संकट और लाखों जनता विस्थापन तथा लाखों जनता भुखमरी का शिकार हो रही है. आर्थिक संकट से उथल–पुथल होने वाला श्रीलंका में दलाली शासकों के खिलाफ तमाम उत्पीड़ित वर्गों, धर्मों व राष्ट्रीयताओं की 20 लाख जनता, विशेषकर महिलाएं सड़कों पर उतरकर महीनोंभर लड़ रहे हैं. मजदूरों की दो बार हड़ताल हुईं. सेना, पुलिस व न्याय व्यवस्थाएं स्थगित हो गयीं. वे कोई भी जन आंदोलनकारियों पर बलप्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है. जून 2022 में आयोजित ब्रिक्स, जी7 व नाटो गठजोड़ों की बैठकों में इस आर्थिक व सामाजिक संकट के प्रति साम्राज्यवादी देशों का रवैया ऐसा था कि उससे उन्हें कोई लेना–देना नहीं है. इससे साम्राज्यवाद और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं व जनता के बीच अंतरविरोध और तेज होता जा रहा है. पिछड़े हुए देशों में साम्राज्यवादियों व दलाल शासकों के खिलाफ जनांदोलनों का विस्तार हो रहा है. साम्राज्यवादी–पूंजीवादी देशों में मजदूर वर्ग, प्रवासी जनता, गैर–श्वेत जाति की जनता और मध्यम वर्ग की जनता पर भी इसका प्रभाव अधिक है. इन देशों में मजदूरों समेत विभिन्न उत्पीड़ित तबकों के दीर्घकालीन जुझारू हड़ताल बढ़ रही हैं.

अमेरिका कमजोर हुई अपनी विश्व आधिपत्य को फिर से हासिल करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा लागू की जा रही फासीवादी नीतियों का असली चेहरा पिछले दो वर्षों में उजागर हो गया. इन नीतियों के खिलाफ अमेरिकी जनता के तीव्र विरोध प्रदर्शन व्यापक हो रहे हैं. हाल ही में महिलाओं का गर्भपात अधिकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त किए जाने के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ी है. अमेरिका ने अफ्गानिस्तान में ड्रोनों से मिसाइल दाग कर अलकायदा के नेता हैदर अल जवहरी की हत्या की. अमेरिका अपनी विश्व आधिपत्य की भौगोलिक व राजनीतिक रणनीति के तहत युद्ध अर्थव्यवस्था को जारी रखते हुए युक्रैन, इज्रैल एवं तैवान को तीन मुख्य केंद्र बनाकर इन्हें नाटो द्वारा समन्वित किया जा रहा है. युक्रैन पर रूसी दुराक्रमण

युद्ध से साम्राज्यवादियों के बीच फिर से शीत युद्ध आरंभ हुआ है. अमेरिकी की हिंद–प्रशांत केंद्रित रणनीति के तहत अपनी औपचारिक प्रतिनिधि और जन प्रतिनिधि मंडल की सभापति नानसी पेलोसी को स्विट्जरलैंड, तैवान, जापान आदि देशों के दौरे के लिए भेजकर वह चीन को उलझाने का कदम उठाया. इस दौरे का चीन द्वारा तीव्र विरोध किए जाने के बावजूद अमेरिका उसे अनसुना किया. फलस्वरूप तैवान द्वीप के चारों तरफ चीनी व अमेरिकी सेनाओं की युद्ध विन्यासों से परिस्थिति तनावग्रस्त हो गयी. अमेरिका ने नाटो, क्वाड, आकस जैसे गठजोड़ों पर आधारित होकर पुनःसंगठित होने का प्रयास करना, रूस व चीन ने हर क्षेत्र में होड़ में लगे रहने की वजह से विश्वभर में युद्ध वातावरण बनी हुई है.

हमारा देश में साम्राज्यवादियों की पिछलग्गू हिंदुत्व फासीवादी मोदी सरकार द्वारा लागू की जा रही वैश्वीकारण नीतियों के कारण रुपया की मूल्य एक डालर के प्रति 79.65 रुपये तक घट गयी. देश कर्ज की दलदल में फंसती जा रही है. 2014 में देश का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपये थे, वह इस 8 वर्षों के मोदी के दिवालिया शासन में 135 लाख करोड़ रुपये हो गया. यानी लगभग हर महीना 83 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा रहा है. इस वर्ष सरकार और 16.61 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है. रुपये का अवमूल्यन के कारण कर्ज में और इजाफा हो रहा है. इसमें एक तिहाई कर्ज अगले 9 महीनों में भुगतान करना होगा. लेकिन हमारा देश की विदेशी मुद्रा 22 जुलाई तक 15 महीनों का स्तर 571.56 बिलियन डालर तक घटा है. इसलिए कर्ज भुगतान के लिए नया कर्ज लेना अनिवार्य है या सरकारी परिसंपत्ति को बेचकर भुगतान करना होगा. अभी तक लिए गए कर्ज पर ब्याज भुगतान के लिए हर वर्ष बजट में 8.2 फीसदी पैसे खर्च किए जा रहे हैं. इस तरह मोदी सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' कहते हुए ही 'दूभर कर्जदारी भारत' व 'पराधीन भारत' का आविष्कार किया. सिर्फ वर्ष 2021 में ही बड़े पूंजीपतियों के लिए 2.02 लाख करोड़ रुपये और उनके द्वारा छिपाये गए कर्ज बकाया के लिए 10.75 लाख करोड़ रुपये भुगतान किया. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार किसका जेब भर रही है.

मोदी के शासन में देश के निर्यात द्वारा आने वाले आय से आयात द्वारा होने वाला व्यय बढ़ने लगी. इसी वजह से व्यापार घाटा चिंताजनक स्तर तक पहुंचा है. इससे आम जनता पर कर का बोझ बढ़ा है. युक्रैन पर रूसी दुराक्रमण युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मूल्य काफी बढ़ी है. दैनिक

उपयोगी चीजों की मूल्य आसमान छू रही हैं. उर्वरक व कीटनाशक दवाइयों की मूल्य, कृषि यंत्रों की मूल्य बढ़कर खेती का खर्च बढ़ा है. मुद्रास्फीति 15 फीसदी से अधिक हो गयी. तमाम महत्वपूर्ण आर्थिक सूचियों में भारत देश खराब स्थान पर है. पिछले 8 वर्षों में खुदरा वृद्धि दर बढ़ नहीं पा रही है. बेरोजगारी काफी बढ़ी है. हाल ही में अमेरिका व यूरोप देशों में अधिक मुद्रास्फीति का नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ा रहे हैं. इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर यकीन नहीं रखा जा रहा है. इसी वजह से विदेशी पूंजी हमारा देश से वापस जा रही हैं. वृद्धि दर बढ़ाने के लिए बाजार में चीजों की मांग बढ़नी चाहिए. मांग बढ़ाने के लिए जनता की क्रयशक्ति बढ़नी चाहिए. इसके लिए बेरोजगारी समस्या को हल करना होगा, वेतन बढ़ाना होगा और कर घटाना होगा. हमारा देश में अब यही कमी है.

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र का रिपोर्ट–2022 के मुताबिक भारत की 71 फीसदी जनता के लिए न्यूनतम पोषक आहार (अनाज, प्रोटीन, साग–सब्जी, फल आदि) उपलब्ध नहीं है. फलस्वरूप देश में हर वर्ष 17 लाख लोगों की मौत हो रही है, ऐसा उस रिपोर्ट ने उजागर किया. कल्याण योजनाओं में कटौतियां बढ़ रही हैं. सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना और कार्पोरेट कंपनियों की जकड़न में फंस जाने की वजह से स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र बलि वेदी पर चढ़े हुए हैं. देश में लगभग 7.8 करोड़ घरों में आज भी बिजली सुविधा नहीं है. 33 फीसदी आबादी रोज एक डालर से कम आय से जिंदगी जी रही है. फलतः विश्व भूखी सूची में हमारा देश अत्यंत नीचे स्थान पर यानी 105वें स्थान पर, मानव विकास सूची में 142वें स्थान पर, विश्व संतोषी सूची में 139वें स्थान पर, विश्व यूनिवर्सिटियों में हमारा देश के यूनिवर्सिटियां निचले श्रेणियों में हैं. भारतीय संविधान बताता है कि गरीबी व भूख को मिटाना है और तमाम नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है और उसके प्रवर्तन नियम कहते हैं कि संपदा एक जगह पर जमा नहीं होने देना सरकारी की जिम्मेदारी है. लेकिन वास्तव में हो रहा है इसका पूरा विपरीत.

देश में पिछले तीन दशकों से शोषक सरकारों द्वारा लागू की जा रही वैश्वीकरण नीतियों की वजह से अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं. देश में 77 फीसदी संपदा 10 फीसदी अमीरों के पास जमा हुआ है. देश में एक सेकंड में दो जन यानी हर वर्ष 6 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे फिसल रहे हैं, यह हाल ही का आक्सफाम रिपोर्ट से उजागर हुआ है. साम्राज्यवाद की देन 'करोना' संकट काल में रोजगार खो

जाना, व्यापारों की दिवालियां, कृषि संकट तेज हो जाना, आदि कारणों से देश में 18 से 20 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे फिसल गए हैं. उसी समय में देश के कुबेर मुकेश अंबानी, गौतम अड़ानी समेत कइयों उद्योगपतियों की संपदाएं बहुत बढ़ी हैं. ये है विश्व में बहुत बड़ी जनतंत्र कहलाने वाला हमारा देश का असली चेहरा.

मोदी सरकार की फासीवादी नीतियों के फलस्वरूप तमाम क्षेत्रों में देश–विदेशी कार्पोरेट कंपनियों की पकड़ बढ़ रही है. उनके 8 वर्ष के शासन में कार्पोरेट कंपनियों के लिए अवरोध बने 1800 कानूनों समाप्त किया गया या उनके हितों के अनुरूप कानूनों में संशोधन किया गया. इस्पात, विद्युत, कोयला, डिजिटल ठेकाएं, मुख्य सड़कें, रेल मार्ग, हवाई अड्डें, बंदरगाह, सार्वजनिक संस्थान, प्राकृतिक संसाधन, लाखों करोड़ रुपये की रियायती, बैंक कर्ज माफी, इस तरह समस्त क्षेत्रों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों, देश के अंबानी, अदानी जैसे बड़े दलाल पूंजीपति दिग्गजों द्वारा लुटवाया जा रहा है. तमाम सेक्टारों में संगठित क्षेत्र घटाकर या समाप्त कर, कैजुअलीकरण को आम नीति के रूप में तब्दील कर रही है.

अंतरराष्ट्रीय व देशीय स्तर पर बढ़ी आर्थिक संकट के कारण सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां दूभर होती जा रही हैं, इससे जनता के अंदर बड़े पैमाने पर असंतोष व्याप्त होगी, इसे दलाली हिंदुत्व शासक भलीभांति जानते हैं. यही वजह है इनके नेता मोदी जनता को गुमराह करने के लिए कई तरह की चालबाजी प्रयोग कर रहा है. 'विकास' के बारे में आडंबरपूर्वक वादे कर रहा है. जनता को भ्रम में डालने और हिंदुत्व फासीवाद व अंध–राष्ट्रवाद बहकाने तथा सामाजिक रूप से उन्हें निष्क्रिय करने के लिए 'देश की सौभाग्य' के बारे में जुमलेबाजी कर रहा है. दरअसल मोदी की सरकारी नीतियां जनता व देश के प्रति पूरी तरह खिलाफ हैं और साम्राज्यवादी बैंकों, बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशनों एवं बड़ा दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के लिए अनुकूल हैं. इनसे शोषण व उत्पीड़न से शिकार मजदूर, किसान, मध्यम वर्गों और उत्पीड़ित सामाजिक तबकों की परिस्थितियां और दूभर हो गयी.

मोदी के नेतृत्व में ब्राह्मणीय हिंदुत्व शक्तियों के शासन में घोर निरंकुश व फासीवादी कानून बनाया जा रहा है. विभिन्न श्रमजीवी जनता और जनवादी व मानवाधिकार के आंदोलन क्रूर दमन से लबालब है. गिरफ्तारियां व झूठी मुठभेड़ लगातार जारी है. देश में जनवादी अधिकारों का हनन आम बात बन गयी है. हमारी पार्टी समेत क्रांतिकारी जन संगठनों, उत्पीड़ित वर्गों, जन समुदायों,

उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं और संसदीय विपक्षी पार्टियों को भी निशाना बना रहे हैं. वर्ष 2022 में सिर्फ कश्मीर में ही सरकारी भाड़े के बलों द्वारा 118 लड़ाकू योद्धाओं की निर्मम हत्या की गयी. भाजपा नेतृत्ववाली केंद्र व राज्य सरकारों के साथ–साथ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी, जनता दल (यू), टीआरएस, राजशेखर रेड्डी कांग्रेस, डीएमके, जेएमएम और सीपीएम नेतृत्ववाली संशोधनवादी गठबंधन द्वारा चलायी जा रही राज्य सरकारें भी फासीवादी नीति लागू करने की होड़ में लगी हुई हैं. फलतः देश में कोई सुनवाई के बगैर 76 फीसदी कैदी वर्षों से जेलों में सड़ रहे हैं. झारखंड में सैक सदस्य कामरेड प्रवीर को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनायी गयी. बिहार में पांच आदिवासी व किसान कामरेडो को सुनायी गयी फांसी की सजा को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के रूप में बदली गयी. लेकिन दंडकारण्य में गोंपाड़ गांव में निर्दोष आदिवासियों की हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को निर्दोष ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट उस केस में आदिवासी पक्ष में न्याय का गुहार लगाने वाले गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपये का जुरमाना लगाया. उसी समय में बुरकापाल केस में पांच वर्षों से जेल में सड़ रहे 121 आदिवासियों को निर्दोष ठहराकर कोर्ट ने उनकी रिहाई की. लेकिन पांच वर्षों से निर्दोषों को जेल में बंदी बनाने के प्रति उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया. उन पर झूठे केस लगाकर पांच वर्षों से जेल में बंदी बनाने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कोर्ट किसी भी तरह का जुरमाना नहीं लगाया. यही है शोषक वर्गों के कोर्टों द्वारा आम तौर पर अपनाने वाला वर्ग न्याय.

देश की 'आजादी' की 75वीं वर्षगांठ को हिंदुत्व शासकों द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करते हुए पिछले एक साल से बहुत ही हंगामेदार प्रचार अभियानों, संभा–संगोष्ठियां चलाए जा रहे हैं. दरअसल 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजों से उनके दलाली पूंजीपतियों व सामंतियों के हाथों सत्ता हस्तांतरण होकर 75 वर्ष बीत गए. लेकिन अभी तक जनता की किसी भी एक बुनियादी समस्या का हल नहीं हो पाया. जनता के जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया. गरीबी, भुखमरी, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे दरिद्रों की संख्या बढ़ रही है. साम्राज्यवादी कार्पोरेटीकरण, साम्राज्यवाद–प्रायोजित विकृत औद्योगिक व कृषि नीतियों के फलस्वरूप देश पूरी तरह पराधीन देश के रूप में तब्दील हो गया. साम्राज्यवादी कार्पोरेटीकरण के जरिए बढ़ रही बुलबुला जैसे विकास को दिखाकर सरकारें जनता को भ्रम

में डालने का प्रयास कर रही हैं. वास्ताव में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवादी और बड़े सामंती वर्गों से बनी प्रतिक्रांतिकारी गठजोड़ देश की उत्पादन शक्तियों का विकास के लिए बड़ा अवरोध बना हुआ है और देश में स्थिर विकास के लिए रुकावट बनी हुई है. फलतः औद्योगिक व कृषि क्षेत्र संकट में फंस गए हैं. किसान जमीन बेच कर बटाईदार या किसान–मजदूर बनते जा रहे हैं. मजदूरी भी नहीं मिलने पर, रोजी रोटी के लिए बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं. बहुराष्ट्रीय कंपनियों, दलाल पूंजीपतियों द्वारा विभिन्न उद्योगों में रोजगार हनन करने वाली टेक्नोलोजी लाने और संगठित क्षेत्र को घटाने की वजह से मजदूर व कर्मचारियों का रोजगार के लिए कोई सुरक्षा नहीं रह गयी. आंदोलनों द्वारा हासिल किए गए मजदूर के अधिकार कुचला गया. आंदोलनरत जनता पर सरकारी सशस्त्र बलों के फासीवादी हमले बढ़ रहे हैं. देश का सैन्यकरण किया जा रहा है. विश्व में बहुत बड़ा जनतंत्र कहलाने वाले इस देश में जनता के लिए किसी भी तरह के मौलिक आजादी व अधिकार नहीं हैं. बोलने का अधिकार, बैठक करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, विरोध प्रकट करने का अधिकार, शिक्षा अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिकार, रोजगार अधिकार, आवास अधिकार, आखिर देश में जीने का अधिकार भी नहीं हैं. देश के संवैधानिक कानूनों व प्रवर्तन नियमों का अमल पर किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया जाता. बेरोजगारी व गरीबी बढ़ाने वाली टेक्नोलोजी पर निर्भर होकर हासिल किए गए लगभग तीन ट्रिलियन डालरों का सकल घरेलू उत्पादन को दिखाकर इसी को देश का विकास के रूप में आधुनिक गोबेल्स मोदी बिना थके प्रचारित कर रहा है. इतना विकास दरअसल हुआ तो देश में खाना, आवास, कपड़ा, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीन, सिंचाई, रोजगार की खोज में जनता की जिंदगियां क्यों दूभर हो गयी हैं? इस 'जनतांत्रिक' देश में मत विरोध प्रकट करने का अधिकार समेत कोई राजनीतिक अधिकार क्यों नहीं है?

मोदी की नजरिये में विकास का मतलब है साम्राज्यवादी नयेऔपनिवेशिक शोषण, दलाल पूंजीवादी व सामंती शोषण को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है. इसलिए 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत मोदी नेतृत्व में हिंदुत्व शासकों द्वारा 'नया भारत' का आह्वान करने का मतलब है, देश को साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों हवाला कर देना; घराना हत्यारों व भ्रष्टाचारियों को निर्दोष घोषित करना, उन्हें संरक्षित करना; देश में प्रमुख जननेता व जननेत्रियों के गले घोंट कर अनिश्चितकालीन जेलों में बंदी बनाना या हत्या करना. उसी समय में निर्दोषों को दोषी ठहराया जाता है. सामाजिक

कार्यकलाप चलाना, मानवाधिकार के लिए लड़ना और सत्य के लिए अवाज उठाना अपराध बन जाता है. यहां मुस्लिमों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं की जिंदगियों की कोई मूल्य नहीं रह जाती है. इस देश में गरीबों के रूप में जन्म लेना शाप बन जाता है. अपने साम्राज्यवादी, दलाली कार्पोरेट आकाओं के लिए आवश्यक जमीन, विद्युत, अनमोल लोह धातु, पानी व लकड़ी की एवज में जंगलों के बगैर अस्तित्व ही नहीं होने वाली आदिवासी जिंदगियों को बेरोकटोक बलि चढ़ाना न्यायसंगत बन जाता है. हमले, परेशानियां, यातनाएं और निर्दोषों की हत्याएं जारी रहेगी. यही है 'नया भारत' का असली चेहरा. नया भारत को हासिल करने के लिए ही भारतीय सैन्य बलों का भगवाकरण व फासिजीकरण करने वाली 'अग्निपथ' योजना बनायी गयी है. टाटा कंपनी के सरकारी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नया संसद भवन पर प्रतिष्ठित किए जाने वाले चार शेर ऐसे फासीवादी हमले का संकेत बनने जा रहे हैं जो दिखने में क्रूर व नुकीले दांत फैलाएं हुए हैं. उनके मुंह इस देश को युद्ध पिपासियों की भूमि में तब्दील करने का इरादा उजागर कर रहा है. साम्राज्यवादी नयेऔपनिवेशियों का दासता करने वाले हिंदुत्व दलाली शासकों से अर्धऔपनिवेशिक व अर्धसामंती भारत को मुक्ति करके ही उत्पीड़ित जनता, तबके व राष्ट्रीयताएं स्वेच्छा से सांस ले सकती हैं. तभी असली नया भारत, जनता की जनतांत्रिक भारत, नवजनवादी भारत को देखा जा सकता है.

**प्यारे कामरेडो व जनता!**

जब तक शोषण, उत्पीड़न, दमन व भेदभाव रहेंगे तब तक विभिन्न उत्पीड़ित वर्गों, तबकों एवं राष्ट्रीयताओं की जनता के वर्ग संघर्ष, जनवादी आंदोलन, राष्ट्रीय–मुक्ति आंदोलन और क्रांतियों का दौर चलता रहेगा. अगर शासक वर्ग और उनकी राजसत्ता द्वारा हर रोज नरसंहार, जनता पर अत्याचार व उनका अपमान किया जाता है, तो अवश्य जनता भगावत करने की ओर प्रेरित हो जाती है. इसलिए क्रांतियों पर स्थायी तौर पर पूर्ण विराम लगाना शासक वर्गों एवं उनकी राजसत्ता के लिए संभव नहीं है. हमारी पार्टी सामाजिक क्रांतियों के प्रति मार्क्सवादी समझदारी व अटूट विश्वास के साथ आज की अनुकूल वस्तुगत परिस्थितियों को पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए प्रतिकूलताओं से उबरने के लिए पहलकदमी लेनी चाहिए, इसके लिए रास्ते ढूंढना चाहिए. एक–एक जगह पर होने वाली एक–एक अनुकूलता को पहचाननी चाहिए. दुश्मन के हमले से अपने आप को संभालने के लिए अनुकूलताओं को सक्षम तरीके से इस्तेमाल करते हुए, कमी–कमजोरियों को सुधारते हुए, पहलकदमी को अपने हाथ में रखना

चाहिए. जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करते हुए वर्ग संघर्षों एवं जनांदोलनों को विकसित करना चाहिए. मार्क्स व एंगेल्स ने वैज्ञानिक क्रांतिकारी सिद्धांत 'मार्क्सवाद' से विश्व सर्वहारा वर्ग और तमाम देशों के श्रमिकों को लैस किए. लेनिन व स्टालिन ने बोल्शेविक पार्टी को दुश्मन के प्रति अभेद्य व फौलाद की तरह निर्माण कर, समाजवादी क्रांति सफल बनाकर, समाजवादी राज्य को स्थापित किए. माओ जनता की सेवा किस तरह की जा सकती हैं? नवजनवादी राज्य व समाजवाद को कैसे स्थापित की जा सकती है? इसे बचाने के लिए सांस्कृतिक क्रांति कैसे निर्माण किया जा सकता है? इसे साबित कर दिखाए. जनता के साथ नजदीकी संबंध स्थापित कर, वर्ग संघर्ष की ज्वालाएं पैदा करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व को बड़े पैमाने पर जनता को गोलबंद करना आवश्यक व जरूरी है. उत्पीड़ित वर्गों, तबकों व राष्ट्रीयताओं की जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक व संगठित किए बगैर और वर्ग संघर्ष की लपटें आग का रूप लिए बगैर पार्टी–पीएलजीए–संयुक्त मोर्चा मजबूत नहीं होंगे, क्रांति की जीत नहीं होगी और सर्वहारा अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यों को जुझारू रूप से नहीं निभा पाएंगे. जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जन गोलबंदी, जनांदोलन, दुश्मन के हमले के खिलाफ जन प्रतिरोध–सशस्त्र प्रतिरोध, जनयुद्ध के बगैर कोई भी जनता की विजय बचाया नहीं जा सकता. दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन के जरिए ही अर्धऔपनिवेश और अर्धसामंती व्यवस्था को ध्वस्त कर सशस्त्र कृषि क्रांति की धुरी पर नवजनवादी क्रांति को सफल बनाया जा सकता है और शोषण, उत्पीड़न, दमन व भेजभाव रहित नवजनवादी भारत देश स्थापित की जा सकती है. इस समझादारी से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें!

- दंडकारण्य, बिहार–झारखंड, पूर्वी बिहार–पूर्वोत्तर झारखंड को आधार इलाका के रूप में विकसित करने के लक्ष्य के साथ काम करेंगे.
- जनाधार बढ़ाएं!
- पार्टी, पीएलजीए एवं क्रांतिकारी जन निर्माणों को मजबूत करें!
- साम्राज्यवाद विरोधी, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी वर्ग संघर्ष को तेज करें!
- छापामार युद्ध व जनयुद्ध को व्यापक व तेज करें!
- रणनीतिक 'समाधान'–प्रहार हमले को हराएं! क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाएं!
- हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ जुझारू आंदोलनों का निर्माण करें!
- झूठा 'नया भारत' नहीं चाहिए! नवजनवादी भारत चाहिए!
- सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयता जिंदाबाद!
- मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद जिंदाबाद!
- भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जिंदाबाद!

**13 अगस्त, 2022**

**केंद्रीय कमेटी**

**भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)**

★★★